

प्रमाण,

मंजुल कुमार जोशी
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 02 / 12 / 2008

विषय:- प्लीजेंट वैली फाउन्डेशन को तहसील अल्मोड़ा के ग्राम डांडा काण्डा, जनपद अल्मोड़ा में चैस्टेबल स्कूल एवं हॉस्टल के निर्माण हेतु 2.00 हेक्टेयर भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2020/पॉत-स्टाम्प सहायक/2007 दिनांक-10.12.07 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्लीजेंट वैली फाउन्डेशन को तहसील अल्मोड़ा के ग्राम डांडा काण्डा, जनपद अल्मोड़ा में चैस्टेबल स्कूल एवं हॉस्टल के निर्माण हेतु 2.00 हेक्टेयर भूमि क्रय की अनुमति उत्तराखण्ड, (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(111) के अन्तर्गत जिलाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा संस्तुत खरारा संख्याओं यथा-ज0वि0ख0ख0स0-4,7,8,9,10,11 तथा 15 मध्ये, क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करती है:-

- 1- क्रेता धारा-129-ख के अर्धीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3- क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दस वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कथनों से जिन्हे लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा। भूमि का उपयोग उरी प्रयोजन (विद्यालय भवन एवं हॉस्टल का निर्माण) के लिए करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है।

यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसी रीतिकृत किया गया था, उससे गिनी किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ अन्य किया गया था उससे गिनी प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य ही जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

- 4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।
 - 5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।
 - 6- शासन द्वारा दी गयी भू कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिनों के लिये वैध होगी।
 - 7- स्थापित किये जाने वाले विद्यालय भवन/हॉस्टल में उत्तराखण्ड राज्य के बच्चों को पच्चीस प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिया जायेगा।
 - 8- उक्त सारथान द्वारा उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
 - 9- किसी दशा में प्रस्तावित कैंटाओं का प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि कय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।
 - 10- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमत्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु साकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
 - 11- योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से निधियाँ व अन्य अनापत्तियाँ/रीतिकृतियाँ प्राप्त कर ली जायगी।
 - 12- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबद्धों का पूर्णतः अनुपालन न होने, गिनी उपयोग करने, उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत रीतिकृति निरस्त कर दी जायेगी।
- कृपया इस सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(गजुल कुमार जाशी)
आवर सचिव।

पू०प०रा०-५३५/समदिनांकित/2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 5- प्लीजेंट वैली फाउन्डेशन, 15 लोअर मून-तल बाधाम गिहार नई दिल्ली-110092
- 6- निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, राधिकालय।
- 7- प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(सन्तोष यडोनी)

अनुसचिव।